सदस्य बनें
सच और सरोकार की पत्रकारिता से जुड़ें
वार्षिक सदस्यता : ₹ 500 मात्र
पूरा वर्ष अखबार निःशुल्क
पैनल विज्ञापन दें
अपने व्यवसाय/संस्था का प्रचार करें 'जन जन विचार' में।
किफायती • प्रभावी • विश्वसनीय
संपर्क : 69001 26012

जन जन की बात जन जन तक
साप्ताहिक
जन जन विचार

D.S. Associates
Sri Om Plaza
2nd Floor, K.C. Road,
Chatribari, Guwahati-1
Phone : 7002682705

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 29 May 2026 :: Vol-20 Year-1 :: शुक्रवार । 29 मई 2026 । शक संवत 1948 । ज्येष्ठ। शुक्ल । त्रयोदशी । :: पृष्ठ-8 । मूल्य – 5 रुपए

जन चिंतन
धनेश्वर चौधरी

कॉकरोच के बहाने

भारतीय राजनीति एक विचित्र दौर से गुजर रही है। कभी देश में आंदोलनों की पहचान सड़कों, नारों और जनसभाओं से होती थी, लेकिन अब असंतोष मीम, व्यंग्य और सोशल मीडिया अभियानों के रूप में सामने आ रहा है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' इसी बदलते दौर का सबसे चर्चित उदाहरण बन चुकी है। पहली नजर में यह केवल इंटरनेट का मजाक लगता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता बताती है कि देश का एक बड़ा युवा वर्ग भीतर से गहरे असंतोष और निराशा से गुजर रहा है।

असल प्रश्न यह नहीं है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' कौन चला रहा है। असली प्रश्न यह है कि आखिर देश के लाखों युवाओं को ऐसी व्यंग्यात्मक राजनीति में अपनी आवाज क्यों दिखाई दे रही है?

आज का युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक सामान्य

शेष पृष्ठ 2 पर

असम में यूसीसी पर मुहर

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

आखिरकार वही हुआ जिसकी पूरी संभावना पहले से जताई जा रही थी। भारी हंगामे, विपक्ष के विरोध, नारेबाजी और वॉकआउट के बीच असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 2026 को पारित कर दिया। सत्ता पक्ष ने इसे 'नए भारत' और 'महिला सम्मान' का कानून बताया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र, संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया।

विधानसभा बनी वैचारिक युद्ध का अखाड़ा

27 मई को असम विधानसभा केवल एक सदन नहीं, बल्कि वैचारिक संघर्ष का बड़ा मंच बन गई। एक तरफ भाजपा नीत एनडीए 'एक देश, एक कानून' का उद्घोष कर रहा था, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर समाज को बांटने और राजनीतिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा था।

हालांकि दो-तिहाई बहुमत से लैस भाजपा सरकार के सामने विपक्ष की आवाज अंतत: कमजोर पड़ गई।

प्रवर समिति की मांग खारिज, विपक्ष वेल में उतरा

विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने जब विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी विधायक वेल में उतर आए।

सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा और 'भारत माता की जय' तथा 'जय श्रीराम' के नारों के बीच आवाज मत से बिल पास कर दिया गया।

यूसीसी में प्रावधान

यूसीसी कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करेगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी, लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, बहुविवाह से जुड़े मामलों में सात साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है।

जनजातीय समुदायों को दी गई छूट

दिलचस्प बात यह रही कि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा है। यानी 'समान कानून' के भीतर भी राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई दी। विपक्ष ने इसी आधार पर सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।

तीसरा राज्य बना असम

उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम भी यूसीसी कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। गोवा में पहले से यूसीसी है।

अल्फा बना रहा नया आर्थिक नेटवर्क, उन्नाव से दो गिरफ्तार

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी/उन्नाव

पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के नेटवर्क अब केवल जंगलों और सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रह गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हुई ताजा गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा-आई) के लिए कथित रूप से फंडिंग करने वाले दो आरोपितों को असम पुलिस ने उन्नाव से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सहारनपुर निवासी नूर मोहम्मद और कानपुर निवासी मोहम्मद सुभान अहमद के रूप में हुई है। दोनों पिछले

शेष पृष्ठ 5 पर

बंगाल : घुसपैठिए लौटने लगे अपने 'देश'

उत्तर 24 परगना के बसीरहाट उपखंड स्थित हाकिमपुर बॉर्डर क्रॉसिंग पर बांग्लादेश लौटने के लिए जुटे पश्चिम बंगाल में रह रहे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक।

जन जन विचार
...✍ कोलकाता

पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन दिनों अजीब बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट की ओर बढ़ते चेहरों में डर, घबराहट और अनिश्चितता साफ नजर आ रही है।

महिलाओं के हाथों में जल्दबाजी में बांधे गए कपड़ों के छोटे-छोटे गठ्ठर, बच्चों की डरी हुई आंखें और रात के अंधेरे में सीमा की ओर बढ़ते परिवार-यह दृश्य केवल पलायन का नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल का संकेत माना जा रहा है।

'होल्डिंग सेंटर' का डर

सूत्रों के अनुसार, राज्य में घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ संभावित सख्त कार्रवाई की चर्चाओं ने उन बांग्लादेशी परिवारों

शेष पृष्ठ 3 पर

बीएसएफ को जमीन सौंपने का वादा पूरा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा से सटे 9 जिलों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि इस जमीन पर अब नई चौकियां, निगरानी पोस्ट और कंटीली तारों की फेंसिंग बनाई जाएगी, ताकि अवैध घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

राज्य सरकार ने अवैध विदेशी नागरिकों को रखने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। शुरुआती चरण में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में ऐसे केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों में संदिग्ध अवैध नागरिकों को अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकेगा। इसके बाद उनकी पहचान और नागरिकता की पुष्टि की जाएगी।

शेष पृष्ठ 5 पर

दिल्ली तक फैला पूर्वोत्तर के उग्रवाद का नेटवर्क!

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के सरगना हाओबिजम दिलीप सिंह की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इस गिरफ्तारी को केवल एक उग्रवादी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के उग्रवादी नेटवर्क की राजधानी

शेष पृष्ठ 7 पर

अंदर पढ़ें

3. मेघालय में 90 फीसदी बॉर्डर फेंसिंग संपूर्ण
4. नतीजों पर सवाल
5. रोज 550 करोड़ का बोझ उठा रहीं तेल कंपनियां
7. पंद्रह साल के वैभव ने हिला दिया आईपीएल!

सड़कों पर मौत का तांडव

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

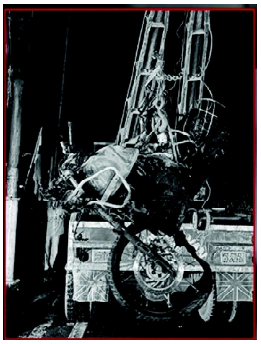

गुवाहाटी एक बार फिर सड़क हादसों की भयावह तस्वीर से दहल उठी। 26 मई को देर रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने न केवल दो परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि गुवाहाटी की सड़कें अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं। तेज रफ्तार, शराब के नशे में ड्राइविंग और प्रशासनिक लापरवाही ने मिलकर शहर को 'दुर्घटना राजधानी' में बदलने की खतरनाक दिशा पकड़ ली है।

पहला हादसा दिसपुर में विधानसभा भवन के सामने आधी रात करीब 12.30 बजे हुआ, जब एक मोटरसाइकिल सवार बिजली के खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक तुरंत आग के गोले में बदल गई। हादसे में धेमाजी निवासी बाखाब राज चुतिया की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें युवक को बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी। कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी राख में बदल गई।

दूसरा हादसा भंगागढ़ इलाके में हुआ, जहां कथित रूप से शराब के नशे में धुत एक तेज रफ्तार कार

चालक ने दूसरी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार आगे चल रहे पानी के टैंकर से भिड़कर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना करने वाली कार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी।

इन हादसों के बाद असम के परिवहन मंत्री चरण बोड़ो ने सड़क सुरक्षा की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि जो भी जरूरी कदम होंगे, तत्काल उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल बैठकों और घोषणाओं से सड़कें सुरक्षित हो जाएंगी?

सरकारी आंकड़े स्थिति की भयावहता को और स्पष्ट करते हैं। जनवरी से मार्च 2026 के बीच असम में 4,219 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 1,008 लोगों की मौत हो गई। यानी औसतन हर दिन 11 से अधिक लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। अकेले गुवाहाटी सहित नौ जिलों में राज्य की लगभग आधी मौतें हुई हैं।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि हादसे अब 'दुर्भाग्य' नहीं बल्कि 'प्रणालीगत विफलता' बन चुके हैं। रात होते ही शहर की सड़कों पर रफ्तार का आतंक शुरू हो जाता है। कई इलाकों में पुलिस की मौजूदगी केवल औपचारिक नजर आती है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नियमों का डर सड़कों से गायब हो चुका है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

कॉकरोच के बहाने

घटना बन चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक दल चुनावों में बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता फिर अकेली पड़ जाती है। ऐसे माहौल में जब व्यवस्था जवाब देने में असफल होती है, तब व्यंग्य प्रतिरोध का हथियार बन जाता है। 'कॉकरोच' दरअसल उसी व्यवस्था पर कटाक्ष है, जिसने युवाओं को उम्मीद के बजाय निराशा दी।

लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है। यदि राजनीति केवल उपहास, ट्रोलिंग और डिजिटल भीड़ तक सीमित हो जाए, तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन निरंतर उपहास लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करता है। जब युवा संसद, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक दलों और प्रशासन-सबको मजाक समझने लगे, तब समाज में अराजक मानसिकता जन्म लेने लगती है।

यही कारण है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' को केवल हास्य कहकर टालना भी गलत होगा और इसे राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र बताना भी उतना ही खतरनाक होगा। यह दरअसल उस गुस्से का डिजिटल रूप है, जिसे वर्षों से अनदेखा किया गया। सत्ता यदि इसे केवल 'ट्रोल गैंग' समझकर दबाने की कोशिश करेगी, तो असंतोष और उग्र होगा। वहीं यदि युवा हर संस्था को बेकार मानकर केवल उपहास की राजनीति में डूब जाएगा, तो वह स्वयं लोकतंत्र को कमजोर करेगा।

आज भारत को दो चरम स्थितियों से बचने की जरूरत है-एक तरफ सत्ता का अहंकार और दूसरी तरफ अराजक असंतोष। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनने का साहस रखे और युवा परिवर्तन के लिए जिम्मेदार संवाद का रास्ता चुने।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि देश की राजनीति मूल मुद्दों से दूर होती जा रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर गंभीर बहस कम हो रही है, जबकि सोशल मीडिया की सनसनी ज्यादा बढ़ रही है। यह स्थिति भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि राजनीतिक दल युवाओं को केवल वोट बैंक समझते रहे, तो आने वाले समय में यही डिजिटल असंतोष बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है।

भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने का दावा करता है। लेकिन यदि वही युवा खुद को व्यवस्था से कटा हुआ महसूस करने लगे, तो यह किसी भी राष्ट्र के लिए चेतावनी है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' शायद कल समाप्त हो जाए, पर उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई पीढ़ी अब केवल भाषणों से संतुष्ट नहीं होगी। वह रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहती है।

अब निर्णय राजनीति को करना है-क्या वह इस व्यंग्य में छिपे दर्द को समझेगी, या हर आलोचना को दुश्मनी मानकर देश को और अधिक अविश्वास की ओर धकेलेगी?

तेरह दिन बाद सकुशल मिला बसंत, परिवार ने जताया आभार

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

पिछले 13 दिनों से लापता चल रहे बसंत के सकुशल मिलने से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवार की ओर से जारी संदेश में बताया गया कि कठिन परिस्थितियों के बीच सभी लोगों के सहयोग, प्रार्थनाओं और सोशल मीडिया पर संदेश साझा करने की वजह से बसंत सुरक्षित वापस लौट आया है। अवकाश कुमार जम्मड़ एवं समस्त जम्मड़ परिवार ने 'जन जन विचार' समेत सभी मित्रों, शुभचिंतकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन 13 दिनों में मिले समर्थन को वे कभी नहीं भूल पाएंगे।

साप्ताहिक राशिफल

29 मई से 4 जून 2026।। विक्रम संवत 2083-**मास** : ज्येष्ठ, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** : त्रयोदशी

मेष — **इस** सप्ताह करियर में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है।

वृषभ — **यह** सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

मिथुन — **कामकाज** में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन सफलता भी मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी। रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

कर्क — **यह** सप्ताह मानसिक शांति और राहत लेकर आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी।

सिंह — **करियर** में पहचान मिलने के योग हैं। हालांकि रिश्तों में थोड़ी उलझन रह सकती है। अहंकार से बचें और धैर्य रखें। धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

कन्या — **पुरानी** परेशानियों से राहत मिलेगी। नौकरी में नई संभावनाएँ बन सकती हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल है।

तुला — **मानसिक** संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

वृश्चिक — **यह** सप्ताह आपके लिए खास रह सकता है। भविष्य की योजनाओं में गंभीरता से काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी लेकिन मानसिक तनाव से बचना होगा।

धनु — **नई** ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। यात्रा के योग बन सकते हैं। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

मकर — **भावनात्मक** रूप से मजबूत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी। परिवार के किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ — **नई** शुरुआत के संकेत हैं। करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा।

मीन — **पुरानी** यादें या भावनाएँ परेशान कर सकती हैं, लेकिन परिवार का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

3 जून (बुधवार) : संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

बांग्लादेश सीमा पर भारत की सबसे बड़ी घेराबंदी लगभग पूरी, मेघालय के मुख्यमंत्री की घोषणा

मेघालय में 90 फीसदी बॉर्डर फेंसिंग संपूर्ण

जन जन विचार
...✍ शिलांग

पूर्वोत्तर में बदलते जनसांख्यिकीय समीकरण, अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मेघालय से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने घोषणा की है कि राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 90 प्रतिशत फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है।

मेघालय की 440 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से करीब 400 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़बंदी पूरी कर ली गई है। अब केवल 40 से 45 किलोमीटर का हिस्सा बाकी बचा है, जहां स्थानीय समस्याओं और गांवों से जुड़े विवादों के कारण काम रुका हुआ है।

मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि कुछ इलाकों में फेंसिंग की लाइन गांवों, खेती की जमीनों और भारतीय क्षेत्र के भीतर से गुजर रही है। इससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। राज्य सरकार फिलहाल प्रभावित गांवों और समुदायों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।

लेकिन इस खबर का महत्व केवल मेघालय तक सीमित नहीं है। यह ऐसे समय में सामने आई है जब केंद्र सरकार ने देशभर में जनसंख्या बदलाव और अवैध

घुसपैठ की जांच के लिए 'हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेज' का गठन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि सीमा क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ, असामान्य जनसंख्या बदलाव और सीमा पार गतिविधियां राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी हैं। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए इन बदलावों के कारण और प्रभाव दोनों की जांच करवाना चाहती है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली यह समिति अगले एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। समिति यह भी सुझाएगी कि अवैध प्रवास, सीमा पार गतिविधियों और जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए कौन से कानूनी और प्रशासनिक कदम जरूरी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि मेघालय में तेजी से पूरी हो रही फेंसिंग केवल सुरक्षा परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर में बदलती राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और जनसंख्या परिवर्तन लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहे हैं। अब केंद्र सरकार इन मुद्दों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है।

हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' नीति, सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ की बढ़ती सक्रियता और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की खबरों ने पूरे पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में मेघालय की यह प्रगति एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।

असम मंत्रिमंडल का विस्तार तीन जून के बाद

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर आखिरकार मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने खुद विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा कि 3 जून के बाद ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल असम के राज्यपाल मंगोलिया दौरे पर हैं और उनके लौटने के बाद ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण संभव होगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और सहयोगी दलों के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर किस विधायक की किस्मत खुलेगी और कौन सत्ता की नई टीम में जगह पाएगा। साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है और कई विभागों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।

असल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से असम मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं लगातार चल रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भाजपा की आगामी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा। खासकर लोकसभा चुनावों से पहले क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश इस विस्तार में साफ दिखाई दे सकती है। ऊपरी असम, बराक घाटी और जनजातीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर रहने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों की मानें तो भाजपा नेतृत्व संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए कुछ युवा और सक्रिय विधायकों को भी मौका दे सकता है। वहीं कई ऐसे विधायक, जो लंबे समय से मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, दिल्ली और दिसपुर दोनों जगह सक्रिय हो चुके हैं।

दिलचस्प बात यह भी है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे बड़े और विवादित विधेयक को विधानसभा से पारित कराने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार का संकेत दिया है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा सरकार की 'नए राजनीतिक संदेश' की तैयारी के रूप में देख रहे हैं।

सिक्किम बना देश का पूर्ण साक्षर राज्य

जन जन विचार
...✍ गंगटोक

पूर्वोत्तर के छोटे लेकिन प्रगतिशील राज्य सिक्किम ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को 'पूर्ण साक्षर राज्य' घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार के 'समाज के सभी लोगों के लिए आजीवन शिक्षा की समझ' मिशन के तहत सिक्किम को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया।

गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम सरकार और राज्य की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल शिक्षा का आंकड़ा नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि साक्षरता समाज में समानता और आत्मविश्वास को मजबूत करती है।

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसे सिक्किम के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

बंगाल : घुसपैठिए लौटने लगे अपने 'देश'

में भय पैदा कर दिया है, जो पिछले कई वर्षों से कोलकाता, दमदम, बारासात, हावड़ा और आसपास के इलाकों में रह रहे थे। सबसे अधिक डर 'होल्डिंग सेंटर' को लेकर बताया जा रहा है। चर्चा है कि अवैध रूप से रहने वालों की पहचान होने के बाद उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा सकता है और बाद में सीमा पार भेजा जा सकता है।

वर्षों से बसे परिवारों में बढ़ी घबराहट

सीमावर्ती क्षेत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से छोटे-छोटे समूहों में लोग सीमा की ओर लौट रहे हैं। इनमें कई ऐसे परिवार भी हैं जो एक दशक से अधिक समय से बंगाल में रह रहे थे। कोई रिक्शा चलाता था, कोई निर्माण मजदूर था, तो कोई चमड़ा कारखानों और छोटे उद्योगों में काम कर रहा था। इन लोगों ने शहरों में अपनी छोटी-छोटी दुनिया बसा ली थी, लेकिन अब माहौल अचानक बदलता दिखाई दे रहा है।

'हम गरीब लोग हैं, जेल नहीं जाना चाहते'

28 वर्षीय नसीम मोल्ला, जो कोलकाता के एक चमड़ा कारखाने में काम करता था, ने कहा कि पहले लगा था केवल कागजों की जांच होगी, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक भी कुछ दिन गायब रहने की सलाह दे रहा है। उसने कहा, 'हम गरीब लोग हैं, जेल नहीं जाना चाहते।'

42 वर्षीय अब्दुल करीम ने बताया कि वह दस साल पहले मजदूरी करने आया था। यहां आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तक बन गया था। उसने चुनावों में वोट भी डाले, लेकिन अब अचानक माहौल बदल गया है।

दूसरी बार दिख रहा ऐसा माहौल

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक साल में यह दूसरा मौका है जब बड़ी संख्या में लोग सीमा की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की खबरों के दौरान ऐसा माहौल बना था।

राजनीति से लेकर सुरक्षा तक बढ़ी बहस

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में बदलते राजनीतिक समीकरण और सीमा सुरक्षा को लेकर बढ़ती सख्ती का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। भाजपा लंबे समय से घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों का मुद्दा उठाती रही है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई की आशंका ने सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बना दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी

सीमा क्षेत्रों में बढ़ती हलचल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वर्षों से पहचान पत्रों और सरकारी दस्तावेजों के सहारे रह रहे लोग अब अचानक खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? सीमा की ओर लौटते इन चेहरों में केवल डर ही नहीं, बल्कि एक टूटती हुई 'झूठी स्थिरता' का एहसास भी दिखाई दे रहा है। बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा वर्षों से चुनावी हथियार रहा है, लेकिन अब पहली बार उसका असर जमीन पर इतने स्पष्ट रूप में नजर आने लगा है।

संपादकीय

बंगाल में बदलती हवा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वह केवल सत्ता परिवर्तन का असर नहीं, बल्कि शासन की शैली बदलने का संकेत भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पद संभालते ही जिस तरह प्रशासनिक सख्ती बढ़ी है, उसने वर्षों से 'कटमनी', 'भाइपो टैक्स' और राजनीतिक संरक्षण में पल रहे गुंडाराज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर सीमावर्ती इलाकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुभव यह बता रहे हैं कि बंगाल की सड़कों पर पहली बार कानून का भय दिखाई देने लगा है।

वर्षों से पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमाओं पर ट्रक चालकों के लिए सफर किसी यातना से कम नहीं था। अवैध वसूली करने वाले गिरोह खुलेआम बांस की बैरिकेडिंग लगाकर ट्रकों को रोकते थे। 'डंडा टैक्स' और 'भाइपो टैक्स' के नाम पर जबरन वसूली होती थी। विरोध करने पर चालकों के साथ मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ और घंटों तक उत्पीड़न आम बात थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब किसके संरक्षण में चल रहा था? क्या पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? या फिर राजनीतिक संरक्षण ने कानून को बंधक बना रखा था?

अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ट्रक चालकों और व्यापारियों का कहना है कि जो लोग कल तक खुलेआम उगाही करते थे, वे अब कार्रवाई के डर से छिपने लगे हैं। अगर यह बदलाव सचमुच स्थायी साबित होता है, तो यह केवल कानून व्यवस्था की जीत नहीं होगी, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर भी चोट होगी जिसने वर्षों तक भय और वसूली को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया था।

सुलगता सवाल आपके विचार

यूपी की नई राजनीतिक बिसात

उत्तर प्रदेश की राजनीति नए समीकरणों की आहट दे रही है। कांग्रेस एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के करीब जाने की कोशिश कर रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने वर्षों तक बसपा की राजनीति का विरोध किया, लेकिन अब भाजपा को रोकने के लिए नए सामाजिक समीकरण तलाश रही है। दिलचस्प यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस के कुछ नेता चुपचाप मायावती तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। लेकिन मायावती ने जिस तरह उन्हें मिलने तक का समय नहीं दिया, उसने साफ कर दिया कि बसपा अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है।

असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उसकी घटती जमीन है। राहुल गांधी भले दलित समाज के बीच सक्रियता बढ़ा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस आज भी अपने दम पर बड़ा जनाधार खड़ा करने में संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि उसे बार-बार क्षेत्रीय दलों के सहारे की जरूरत पड़ रही है।

मायावती का रुख भी कम दिलचस्प नहीं है। वह जानती हैं कि भाजपा विरोधी राजनीति में उनकी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वह यह भी समझती हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों के साथ जाने का मतलब अपने पारंपरिक वोट बैंक को जोखिम में डालना हो सकता है।

नतीजों पर सवाल

जन जन विचार
...✍ अजय बोकिल

देश में मेडिकल में प्रवेश के लिए 'नीट' परीक्षा में पेपर लीक का विवाद थमा भी नहीं था कि अब सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसम) प्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। जिस भारी संख्या में असंतुष्ट परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन, स्कैन कॉपी और मार्क्स वेरीफिकेशन की मांग कर रहे हैं, उससे तो इस परीक्षा की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिह्न लग रहा है। परीक्षार्थियों के अलावा उनके अभिभावक भी परेशान हैं।

नतीजों में गड़बड़ी का यह सबसे बड़ा घोटाला होता दिख रहा है। क्योंकि सीबीएसई की 12 वीं बोर्ड परीक्षा में देश भर के 17 लाख 68 हजार परीक्षार्थी बैठे थे। इनमें से 4 लाख से ज्यादा यानी एक चौथाई परीक्षार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और मार्किंग पर संदेह जताते हुए पुनर्मूल्यांकन और स्कैन कॉपी की मांग की है। हालांकि रिवेल्युएशन के आवेदन आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होती है। इस बार तो उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग में गड़बड़ी और गलत कॉपी स्कैनिंग ने लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। जिनके मार्क्स अपेक्षा से बहुत कम आए हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। शिकायतों का आलम यह है कि सीबीएसई का पोर्टल बार-बार क्रैश हो रहा है।

हैरानी की बात तो यह है कि वेदांत श्रीवास्तव जैसे 12वीं के परीक्षार्थी ने अपनी स्कैन कॉपी ही गलत बताई और सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली तो भी उसे सोशल मीडिया में 'पाकिस्तानी' कह कर ट्रोल किया गया। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से 12 बोर्ड की उत्तीर्ण दर में 3.19 फीसदी की गिरावट आई है।

शिकायतकर्ता परीक्षार्थियों का कहना है कि कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के कारण उनके नंबर अपेक्षा से बहुत कम आए हैं। दरअसल ओएसएम एक डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेस है। इसमें कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया जाता है। सबसे पहले आंसर शीट को हाई-स्पीड स्कैनर से स्कैन किया जाता है फिर डिजिटल फॉर्मेट यानी पीडीएफ अथवा इमेज में बदला जाता है। स्कैन्ड कॉपियों को सिक्योर सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाता है। कॉपी चेक करने वाले टीचर लैपटॉप या टैबलेट पर लॉगिन करके स्क्रीन पर ही आंसर देखते हैं और डिजिटल पेन या माउस से मार्क्स देते हैं।

सिस्टम खुद ही मार्क्स जोड़ता है और दावा है कि इसमें टोटलिंग एरर नहीं होता। बताया जाता है कि ऑन लाइन कॉपी जांचने वाले कई शिक्षकों ने स्कैन की गई आंसर शीट्स के ब्लर (अस्पष्ट) होने और तकनीकी समस्याओं को लेकर शिकायते की थीं। लगता है कि ब्लर कॉपियों को पढ़े बिना ही अंदाज से नंबर दे दिए गए। नुकसान मेधावी विद्यार्थियों का हो गया। परीक्षार्थियों ने बड़े पैमाने पर भुगतान संबंधी दिक्कतों, धुंधली स्कैन कॉपियों, गायब पन्नों और यहां तक कि गलत उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड होने जैसी समस्याओं की शिकायत की है। हालांकि सीबीएसई का दावा है कि ओएसएम तकनीक पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़िया सामने आ रही हैं, उससे कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यह कि जब कॉपी की डिजीटल चेकिंग की व्यवस्था की विश्वसनीयता पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाती, तब इसे इतनी जल्दबाजी में लागू करने का मकसद क्या था?

शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो, इसमें दो राय नहीं, लेकिन नई व्यवस्था लागू करने के पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेने की जिम्मेदारी किसकी है? और यह व्यवस्था सीधे 12 बोर्ड में लागू करने का तुगलकी निर्णय लेने का क्या मतलब है? यह सिस्टम भी परीक्षा के एक महीने पहले ही लागू किया गया। समझदारी तो इसी में थी कि पहले इसे पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर किसी एक जोन में बिना बोर्ड परीक्षा वाली किसी क्लास की लोकल परीक्षा में लागू कर इसकी खामियों को समझकर उन्हें दूर किया जाता और फिर धीरे-धीरे उसे समूची बोर्ड परीक्षा में लागू किया जाता।

हैरानी की बात तो यह है कि वेदांत श्रीवास्तव जैसे 12वीं के परीक्षार्थी ने अपनी स्कैन कॉपी ही गलत बताई और सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली तो भी उसे सोशल मीडिया में 'पाकिस्तानी' कह कर ट्रोल किया गया। इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से 12 बोर्ड की उत्तीर्ण दर में 3.19 फीसदी की गिरावट आई है।

गौरतलब है कि स्कूली शिक्षा में 12 की बोर्ड परीक्षाएं बच्चों के भविष्य की दिशा और नींव तैयार करती हैं। अगर उसी में भारी धांधली हो और उस धांधली का घुमा-फिराकर बचाव किया जाए तो लोग किस पर भरोसा करें? भारत में अभी तक हाथ से लिखी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षकों द्वारा मैनुअली जांचने की ही परंपरा रही है। खामियां उसमें भी रही हैं, फिर भी तुलनात्मक रूप से यह व्यवस्था सर्वमान्य रही है, क्योंकि उसमें मनुष्य का विवेक केंद्र में रहता है। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की तेजी से, ज्यादा तकनीकी और कथित रूप से पारदर्शी तरीके से कराने के नाम पर जो कुछ किया है, उससे तो पूरे सिस्टम की प्रामाणिकता और निष्पक्षता पर ही सवालों के घेरे में है।

शिक्षा प्रणाली में बदलते जमाने के हिसाब से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आज दुनिया के सौ देशों में डिजीटल वेल्युएशन सिस्टम लागू है। लेकिन उसे लागू करते समय पूरी सावधानियां बरती जाती हैं और उसे फुलप्रूफ बनाया जाता है। लेकिन लगता है कि सीबीएसई ने इसे तुगलकी अंदाज में और वो भी सीधे और 12 बोर्ड जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में लागू कर दिया। जबकि केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक संघों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि नए सिस्टम को लेकर शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

नई व्यवस्था को हडबड़ी में लागू करने का नतीजा है कि इस बार सीबीएसई की 98 लाख 60 हजार उत्तर पुस्तिकाओं में से 11 लाख 31 हजार कॉपियों के मार्क्स वेरिफिकेशन के आवेदन आ चुके हैं। यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। जिस नतीजे पर परीक्षार्थी को ही भरोसा नहीं है, उसका क्या औचित्य है? सीबीएसई नतीजों पर मचे देशव्यापी बवाल के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे गंभीरता से लेते हुए ओएमएस सिस्टम की प्रामाणिकता की जांच आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञो से कराने की घोषणा की है, लेकिन जिन बच्चों का नुकसान हो गया है, उनका क्या? व्यवस्था को सुधारने, तेज और पारदर्शी बनाने के नाम पर सीबीएसई ने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका जिम्मेदार कौन है?

एसआईआर सही : सुप्रीम कोर्ट

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को सही ठहराते हुए चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी सूची चार सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय को भेजी जाए, ताकि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उनकी नागरिकता पर फैसला किया जा सके।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन को लेकर सख्ती बढ़ रही है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें नोटिस देकर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

अदालत ने कहा कि यदि जांच के बाद संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक पाए जाते हैं, तो उनके नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों का निपटारा आगामी लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले किया जाना बेहतर होगा।

वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया 23 साल के लंबे अंतराल के बाद की जा रही है और इसका उद्देश्य वोटर सूची में मौजूद गंभीर विसंगतियों को दूर करना है।

अदालत ने माना कि इतने बड़े स्तर पर चल रही इस प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, इसलिए इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता।

वोटर सत्यापन के दौरान मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर उठाए गए सवालों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दस्तावेजों का वर्गीकरण स्पष्ट और तार्किक आधार पर किया गया है, जिसका सीधा संबंध वोटर लिस्ट की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने से है।

‘न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार, जज कोई पवित्र गाय नहीं’

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

मद्रास हाई कोर्ट ने एक तमिल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज करते हुए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की मौजूदगी को स्वीकार किया है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने कहा कि ‘जज कोई पवित्र गाय नहीं हैं’ और न्यायपालिका को भी आलोचना व सार्वजनिक जांच का सामना करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका में पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी हैं। साथ ही यह भी टिप्पणी की कि कुछ वकीलों की मिलीभगत के बिना न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट भ्रष्ट लोगों पर लगातार नजर रखता है और समय-समय पर कार्रवाई भी करता है।

मामला एक तमिल फिल्म से जुड़ा था, जिसमें एक जज को रिश्वत लेते और नशीले पदार्थों का सेवन करते दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे न्यायपालिका की छवि खराब करने वाला बताते हुए फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कलात्मक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

बीएसएफ को जमीन सौंपने ...

सरकार ने केंद्र के सहयोग से नई डिपोर्टेशन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। योजना के अनुसार, पहचान होने के बाद अवैध नागरिकों को बीएसएफ के हवाले किया जाएगा।

इसके बाद बीएसएफ सीधे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) से संपर्क कर नागरिकता सत्यापित करेगी और संबंधित लोगों को सीमा पार भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा।

अल्फा बना रहा नया आर्थिक ...

करीब आठ महीनों से उन्नाव के सदर क्षेत्र में छिपकर रह रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों अल्फा-आई के लिए आर्थिक नेटवर्क तैयार करने और फंडिंग जुटाने में सक्रिय थे।

असम पुलिस की तिनसुकिया क्राइम ब्रांच लंबे समय से दोनों की तलाश में थी। दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सर्विलांस के जरिए दोनों की लोकेशन उन्नाव में मिली, जिसके बाद असम पुलिस ने स्थानीय स्वाट टीम और उन्नाव पुलिस की मदद से संयुक्त अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी किराए के मकान में रह रहे थे और अपनी गतिविधियों को बेहद गोपनीय तरीके से चला रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से असम पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गया। इसके बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच असम ले जाया गया।

इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अल्फा का नेटवर्क देश के अलग-अलग राज्यों तक कैसे फैल रहा है? सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या दोनों केवल फंडिंग तक सीमित थे या फिर उनके संपर्क किसी बड़े आतंकी और उग्रवादी मॉड्यूल से भी जुड़े हुए थे।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में पूर्वोत्तर से जुड़े कई संदिग्ध नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सक्रिय पाए गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि उग्रवादी संगठनों ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। सीधे हथियारबंद गतिविधियों के साथ-साथ वे आर्थिक नेटवर्क, हवाला, फर्जी पहचान और देश के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षित ठिकाने तैयार करने पर भी काम कर रहे हैं।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों पर उग्रवादी संगठन को फंडिंग करने का आरोप है, वे महीनों तक दूसरे राज्यों में सामान्य नागरिकों की तरह रह रहे थे। इससे सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय खुफिया तंत्र पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल असम पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही हैं। जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि उनके संपर्क किन-किन लोगों से थे और क्या देश के अन्य हिस्सों में भी अल्फा-आई का आर्थिक नेटवर्क सक्रिय है।

रोज 550 करोड़ का बोझ उठा रहीं तेल कंपनियां

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बीच केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियां देश की जनता को राहत देने के लिए बड़ा आर्थिक बोझ उठा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर रोजाना करीब 550 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं, ताकि महंगाई की पूरी मार सीधे आम आदमी पर न पड़े।

सरकार का साफ कहना है कि वैश्विक संकट की कीमत देश के मध्यम वर्ग, किसानों और आम उपभोक्ताओं से नहीं वसूली जाएगी। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद भारत में खुदरा कीमतों को पूरी तरह नहीं बढ़ाया गया है।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह राहत कितने दिनों तक जारी रह पाएगी? क्योंकि दुनिया भर में तेल बाजार में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है और अगर पश्चिम एशिया संकट लंबा खिंचता है, तो सरकार और तेल कंपनियों दोनों पर दबाव और बढ़ सकता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार फिलहाल सरकारी तेल कंपनियां खुद नुकसान उठाकर घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रख रही हैं। हालांकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय की जा रही हैं। सरकार को डर है कि यदि वैश्विक कीमतों का पूरा असर सीधे जनता पर डाल दिया गया, तो महंगाई की नई लहर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

इस बीच एक नई समस्या भी सामने आई है। सरकार ने आरोप लगाया है कि कुछ औद्योगिक उपभोक्ता सस्ते खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदकर राहत योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। निजी तेल कंपनियों के यहां डीजल बिक्री में करीब 38 प्रतिशत गिरावट आई है, क्योंकि उनकी कीमतें सरकारी पंपों से अधिक हैं। इसके कारण सरकारी पेट्रोल पंपों पर दबाव तेजी से बढ़ा है।

स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष निगरानी दल बनाने के निर्देश दिए हैं। इन टीमों को कालाबाजारी, अवैध भंडारण और खुदरा ईंधन के गलत इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

जन जन की बात जन जन तक — साप्ताहिक
जन जन विचार
RNI Regd No. ASMUL/25/A2367

Head Office : Golapi Market, 1st Floor, Beltola, Guwahati 781029
Branch Office : JanJan Vichar, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Contact : 69001 26012
Email: official.janjanvichar@gmail.com
Website: WWW.janjanvichar.in

ग्राहक सदस्यता फॉर्म

ग्राहक विवरण

पूरा नाम : ....
पूरा पता : ....
मोबाइल : .... ह्वाट्सएप ....
ई-मेल (यदि हो) : ....

सदस्यता विवरण
अवधि : 1 वर्ष शुल्क : रु. 500/- मात्र

सदस्यता के साथ विज्ञापन लाभ
- सालभर (52 अंक) का अखबार नि:शुल्क मिलेगा
- एक नि:शुल्क विज्ञापन (10 सेमी. x 3 कॉलम)
- विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ग्राहक की सुविधा अनुसार

भुगतान विवरण
☐ यूपीआई ☐ बैंक ट्रांसफर
Bank Details
JAN JAN VICHAR
Bank : HDFC, Branch : Guwahati
A/C No. 50200116979015
IFSC : HDFC0000264
इस क्यूआर कोड को स्कैन कर जन जन विचार के बैंक खाते में सीधे भुगतान कर सकते हैं।
(कृपया उपरोक्त में किसी एक माध्यम से ही भुगतान करें।)
भुगतान तिथि : .... रसीद संख्या:..............

घोषणा

मैं स्वेच्छा से जन जन विचार साप्ताहिक अखबार की एक वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता/करती हूँ एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर : तिथि :

कार्यालय उपयोग हेतु

सदस्यता क्रमांक: .... भुगतान प्राप्त रसीद संख्या:.............. प्राप्तकर्ता का नाम : ....
तिथि : .... हस्ताक्षर : ....

इग्नू के जुलाई सत्र के लिए प्रवेश शुरू

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन एवं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा के साथ नौकरी, व्यवसाय या अन्य कार्यों को संतुलित करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इग्नू की ओर से स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), डिप्लोमा और विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन प्रोग्राम या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड का चयन कर सकते हैं। यही कारण है कि देशभर के लाखों विद्यार्थी हर वर्ष इग्नू के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। अभ्यर्थियों को सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आवश्यक विवरण भरकर संबंधित पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि अभ्यर्थी स्वयं ही आसानी से फॉर्म भर सकें। इग्नू प्रशासन के अनुसार, आवेदन के बाद यदि कोई छात्र किसी कारणवश प्रवेश वापस लेना चाहता है, तो उसे फॉर्म विड्रॉ करने की सुविधा भी दी जाएगी।

जागीरोड महाविद्यालय और शब्द भारती के बीच एमओयू हस्ताक्षरित

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

जागीरोड महाविद्यालय (ऑटोनोमस) और शब्द भारती (हिंदी संसाधन केंद्र), गुवाहाटी के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य भाषा प्रौद्योगिकी, रोजगारमुखी प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, संगोष्ठियों तथा शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस एमओयू के तहत महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अकादमिक कार्यशालाएं, संगोष्ठियां तथा श्रीमंत शंकरदेव अध्ययन केंद्र के बहुआयामी विकास से जुड़े कार्य भी प्रारंभ किए जाएंगे। इन गतिविधियों में असम सहित पूर्वोत्तर के अन्य शैक्षिक संस्थानों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। समझौते में उल्लिखित कार्यक्रमों का संचालन जागीरोड महाविद्यालय के सहयोग से शब्द भारती द्वारा किया जाएगा।

समझौते पर जागीरोड महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य डॉ. भवेन चंद्र नेउग, शंकरदेव अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉ. कणिमा पाठक, डॉ. गार्गी फुकन, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश डेका तथा आइक्यूएसी समन्वयक डॉ. सीआर सरकार ने हस्ताक्षर किए। वहीं शब्द भारती की ओर से उपाध्यक्ष कालीचरण बासफोर, सचिव डॉ. मोहन कोईराला तथा पीजी पाठ्यक्रम समन्वयक निर्माली देवी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।

एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जागीरोड महाविद्यालय के शंकरदेव अध्ययन केंद्र, हिंदी विभाग और शब्द भारती के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए 'जीविकामूलक परामर्श प्रदान कार्यक्रम' का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वर्तमान समय में तकनीकी रोजगार, भाषा कौशल और रोजगार के नए अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

बीएसएनएल में जेटीओ के 100 पदों पर भर्ती

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में जूनियर टेलिकॉम ऑफिसर (जेटीओ) के 100 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

जूनियर टेलिकॉम ऑफिसर पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने टेलिकम्युनिकशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो या एमएससी (कंप्यूटर साइंस) डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 3 जुलाई 2027 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जायेगा। जो अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में निर्धारित कटऑफ प्राप्त करेंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयनित होने वाले युवाओं को 16400 से लेकर 40500 रुपए प्रतिमाह सैलरी प्रदान की जाएगी।

इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 2000 रुपए फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग को फीस के रूप में 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

विश्व पर्यावरण दिवस की गतिविधि

प्यारे बच्चो,

आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आशा है, आप भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाओगे। इस मौके पर हम आपको एक गतिविधि दे रहे है॥ आप एक पौधा रोपें और उसे रोपते हुए अपनी एक तस्वीर हमें 6900126012 पर अपने नाम, स्कूल और कक्षा लिखकर भेंज दें। हम उसे प्रकाशित करेंगे।

गुरु अर्जुन देव जी : धर्म और मानवता के महान शहीद

गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस सिख धर्म के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक अवसर माना जाता है। यह दिवस हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के आस-पास मनाया जाता है। सिख समुदाय इस दिन को 'शहीदी गुरुपर्व' के रूप में श्रद्धा, सेवा और समर्पण के साथ मनाता है। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे और उन्हें सिख इतिहास का पहला महान शहीद माना जाता है, जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल में हुआ था। वे चौथे सिख गुरु गुरु राम दास और माता भानी जी के पुत्र थे। 1581 में वे सिखों के पांचवें गुरु बने। गुरु बनने के बाद उन्होंने सिख धर्म को संगठित और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए।

उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता और सिख समुदाय की शक्ति से मुगल सत्ता चिंतित हो गई। इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहांगीरी' में भी गुरु जी के प्रभाव का उल्लेख किया है।

गुरु अर्जुन देव जी पर कई प्रकार के दबाव डाले गए —

इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, आदि ग्रंथ से कुछ अंश हटाने का दबाव बनाया गया, भारी जुर्माना लगाया गया।

लेकिन गुरु जी ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया।

1606 में लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें भीषण गर्मी में तपते तवे पर बैठाया गया, शरीर पर गर्म रेत डाली गई और अत्यंत क्रूर यातनाएं दी गईं। इसके बावजूद उन्होंने धैर्य और शांति नहीं छोड़ी।

कहा जाता है कि उस समय भी उनके मुख से यह वचन निकला- *'तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे।'*

अंततः 30 मई 1606 को उन्होंने शहादत प्राप्त की। यह घटना सिख इतिहास में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और सत्य के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक बन गई।

पंद्रह साल के वैभव ने हिला दिया आईपीएल!

क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटा, 97 रन की तूफानी पारी से क्रिकेट जगत दंग

जन जन विचार
...✍ खेल डेस्क

आईपीएल 2026 में अगर किसी एक नाम ने पूरे क्रिकेट जगत को सबसे ज्यादा चौंकाया है, तो वह है 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का 14 साल पुराना महारिकॉर्ड भी टूट गया।

महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी अब एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2012 में 59 छक्के जड़े थे। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट को एक नया 'सिक्सर किंग' मिल चुका है।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में वैभव ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। मैदान के चारों ओर चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने केवल 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक ही नहीं, बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी हैरान रह गए।

वैभव ने केवल रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का अगला दौर अब निडर और विस्फोटक बल्लेबाजों का होने वाला है। उनकी 97 रन की पारी केवल 29 गेंदों में आई, जिसमें पांच चौके और 12 विशाल छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 334.48 का रहा।

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वैभव क्रिस गेल के सबसे तेज आईपीएल शतक के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल एक गेंद दूर रह गए। गेल ने 30 गेंदों में शतक लगाया था, जबकि वैभव 29 गेंदों में 97 रन बनाकर आउट हो गए। अगर वह एक गेंद और खेल लेते, तो आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी उनके नाम हो सकता था।

इस मैच में वैभव ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह आईपीएल प्लेऑफ या नॉकआउट मुकाबले में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने केवल 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी की।

इतना ही नहीं, वैभव आईपीएल इतिहास में 20 से कम गेंदों में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने निकोलस पूरन की बराबरी की, जबकि इस सूची में शीर्ष पर अभिषेक शर्मा हैं।

पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी के मामले में भी वैभव ने नया इतिहास रच दिया। वह आईपीएल में शुरुआती छह ओवरों के भीतर पांचवीं बार 50+ स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ दिया, जबकि शीर्ष पर डेविड वॉर्नर हैं।

क्रिकेट जगत अब वैभव सूर्यवंशी को केवल 'युवा प्रतिभा' नहीं, बल्कि भविष्य का सुपरस्टार मानने लगा है। जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ उन्होंने दुनिया के बड़े गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने यह साफ कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को आने वाले वर्षों के लिए एक नया मैच विनर मिल चुका है।

आईपीएल 2026 में वैभव की यह पारी केवल रिकॉर्डबुक का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि इसे उस पल के रूप में याद किया जाएगा जब भारतीय क्रिकेट ने अपने अगले बड़े सुपरस्टार की धमाकेदार एंट्री देखी।

भारतीय खेल जगत को झटका : एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता रणधीर सिंह नहीं रहे

नई दिल्ली। भारतीय खेल जगत ने 27 मई को अपना एक चमकता सितारा खो दिया। एशियाई खेलों में भारत को शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिग्गज खिलाड़ी और वरिष्ठ खेल प्रशासक रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। खिलाड़ी, कोच, खेल प्रशासक और खेल प्रेमी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

बताया गया है कि रणधीर सिंह लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। वह कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और बाद में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली।

रणधीर सिंह केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि भारतीय खेल व्यवस्था के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। उन्होंने उस दौर में भारतीय शूटिंग को नई पहचान दिलाई, जब देश में इस खेल को सीमित संसाधनों और कम लोकप्रियता के बीच संघर्ष करना पड़ता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने भारतीय निशानेबाजी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया। उनकी इस उपलब्धि को भारतीय शूटिंग इतिहास का मील का पत्थर माना जाता है। खेल करियर के बाद भी उन्होंने खेल प्रशासन में अपनी मजबूत भूमिका निभाई। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक रहा।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

दिल्ली तक फैला पूर्वोत्तर के उग्रवाद ...

तक पहुंच के गंभीर संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मणिपुर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

'विशेष बैठक' के लिए दिल्ली आने की आशंका

सूत्रों के मुताबिक, हाओबिजम दिलीप सिंह दिल्ली किसी 'विशेष बैठक' के लिए आया था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह किन लोगों से मिलने वाला था और उसका असली मकसद क्या था।

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि राजधानी में किसी बड़े नेटवर्क को सक्रिय करने या संपर्क मजबूत करने की कोशिश चल रही थी। इसी वजह से जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर मणिपुर के काकचिंग ले जाया गया। वहां उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने एक एके-47 राइफल, अमोघ और एम-5 राइफल सहित बड़ी संख्या में कारतूस जब्त किए हैं। बरामद हथियारों ने एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है।

यूएपीए के तहत दर्ज हैं कई मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दिलीप सिंह के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। माना जा रहा है कि वह पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी नेटवर्क के प्रमुख चेहरों में से एक है और कई गतिविधियों के संचालन में उसकी भूमिका रही है।

क्या दिल्ली में तैयार हो रहा था नया नेटवर्क ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर तक एक प्रतिबंधित संगठन का सरगना कैसे पहुंच गया? क्या यह केवल एक गुप्त बैठक थी या फिर राजधानी में किसी बड़े नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश? सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं। दिल्ली और अन्य राज्यों में संदिग्ध संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है।

बदल रहा है पूर्वोत्तर के उग्रवाद का स्वरूप

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों की कार्यशैली बदल गई है। अब ये संगठन केवल जंगलों और सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि बड़े शहरों में आर्थिक, लॉजिस्टिक और संपर्क नेटवर्क विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में मणिपुर से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क, हथियार सप्लाई और संदिग्ध गतिविधियों के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा संकेत

राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर ऐसे समय में जब देश सीमा पार आतंकवाद, अवैध हथियारों और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे यह पता लगाएं कि दिलीप सिंह का नेटवर्क केवल मणिपुर तक सीमित था या उसके तार देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हुए हैं।

भारत ने खोजा चांद पर 'बर्फ का खजाना'

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चंद्रयान-2 मिशन ने चांद को लेकर एक और बड़ा रहस्य उजागर किया है। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के बेहद ठंडे और अंधेरे क्रेटरों के नीचे बर्फ के मजबूत संकेत खोजे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतरिक्ष मिशनों के लिए ईंधन तैयार करने की दिशा में गेमचेंजर साबित हो सकती है।

यह खोज चंद्रयान-2 ऑर्बिटर में लगे 'डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार' उपकरण से मिले डेटा के आधार पर की गई है। यह माइक्रोवेव इमेजिंग तकनीक चंद्र सतह के नीचे तक जांच करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटरों का अध्ययन किया, जिनमें 'फॉस्टिनी क्रेटर' के भीतर स्थित लगभग 1.1 किलोमीटर चौड़ेएक छोटे क्रेटर में बर्फ के सबसे मजबूत संकेत मिले हैं।

चंद्रयान-2 की खोज से दुनिया हैरान

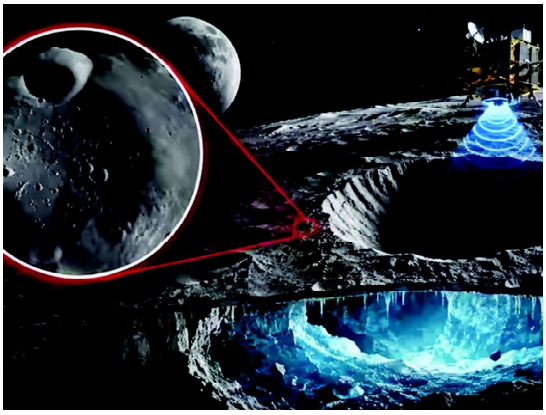

क्रेटर की संरचना ने बढ़ाया वैज्ञानिकों का भरोसा

शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्रेटर में 'लोबेट-रिम मॉर्फोलॉजी' जैसी विशेष संरचना भी देखी गई, जो किसी बहाव जैसी आकृति को दर्शाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संकेत हो सकता है कि उल्कापिंड का प्रभाव चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद बर्फ-समृद्ध परत तक पहुंचा था। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस खोज को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

ध्रुवीय इलाकों में पानी की संभावना मजबूत

यह रिसर्च उन बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों को और मजबूत करती है जिनमें चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी या बर्फ की मौजूदगी की संभावना जताई गई है। इससे पहले भी चंद्रयान-2 के अध्ययन में चंद्र सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल के संकेत मिले थे। हाल के वर्षों में ऑर्बिटर ने हाई-रेजोल्यूशन पोलर मैप्स तैयार किए हैं, जिनकी मदद से बर्फ वाले क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।

डीएफएसएआर बना तकनीकी उपलब्धि

इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 का डीएफएसआर एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह चांद का अध्ययन करने वाला दुनिया का पहला पूर्ण पोलरिमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो एल-बैंड और एस-बैंड दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। 2019 में चंद्र कक्षा में पहुंचने के बाद से यह ऑर्बिटर हजारों डेटा सेट तैयार कर चुका है, जिनसे चांद की सतह और उसकी संरचना को समझने में मदद मिली है।

मून मिशन के लिए गेमचेंजर हो सकती है खोज

विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर बर्फ की मौजूदगी भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। पानी की बर्फ को पीने के पानी, ऑक्सीजन और यहां तक कि रॉकेट ईंधन में भी बदला जा सकता है। ऐसे में यह खोज लंबे समय तक चांद पर मानव मौजूदगी कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

चुटकुले

एक बार पत्नी गुस्से में अपने पति से कह रही थी

पत्नी (गुस्से में)- अरे देख लेना तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी

पति- अरे ठीक है, वैसे भी मैं हर जगह तेरे साथ आना भी नहीं चाहता हूं।

एक भिखारी रास्ते में एक राहगीर से कह रहा था

भिखारी: अरे जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूं मैंने रुपए कमाने के सौ तरीके नामक किताब लिखी है

राहगीर : अरे तुम फिर भी भीख क्यों मांगते हो

भिखारी : क्योंकि यह उस किताब में बताया गया सबसे आसान तरीका है

एक कर्मचारी ने बॉस से पूछा-

सर, आप ऑफिस में शादीशुदा पुरुषों को ही क्यों रखते हैं?

बॉस : क्योंकि, उन्हें जलील होने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती।

भोजपुरी से बॉलीवुड तक अक्षरा सिंह का जलवा

अक्षय कुमार संग 'घिस घिस घिस' ने मचाया धमाल

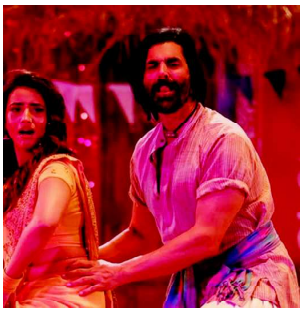

भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। वजह है बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ उनकी धमाकेदार मौजूदगी। फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के नए भोजपुरी अंदाज वाले गाने 'घिस घिस घिस' ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर धूम मचा दी है। गाने में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर बॉलीवुड के बड़े मंच तक पहुंची अक्षरा सिंह ने इस गाने की सफलता पर अपने फैंस का दिल से आभार जताया है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के साथ तस्वीर साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा कि एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि उसके काम को लोगों का प्यार मिले। उन्होंने फैंस से इस गाने को 'मैसिव हिट' बनाने की अपील भी की।

'घिस घिस घिस' की सबसे खास बात यह है कि इसमें भोजपुरी संस्कृति और बॉलीवुड मसाले का जबरदस्त मेल दिखाई देता है। अक्षय कुमार जहां छोटे कुर्ते और पजामे में देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षरा सिंह साड़ी में पूरी तरह भोजपुरी रंग में रंगी दिखाई देती हैं।

पूर्वांचल प्रिंट्स की ओर से राजनाथ पाल द्वारा जीएमसीएच रोड, हरबाला मार्केट, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005 से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपर्क : 69001 26012
ई-मेल:official.janjanvichar@gmail.com, वेबसाइट: www.janjanvichar.in
● कार्यकारी संपादक : सुभाष कुमार चौधरी ●संपादक : धनेश्वर चौधरी